[अध्यक्ष महोदय]

चाहिये, और यह पार्लियामेंट रहनी चाहिये। हमारे और आप जैसे आते जाते रहेंगे, लेकिन Parliament must have the dignity of its own

13.23 hrs.

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) अध्यक्ष जी, मै आप की इजाजत से एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। शिक्षा मन्त्रालय के अनुदान की मांगों पर जब 4 अप्रैल को बहस हो रही थी तो श्री चन्द्र पन ने मेरे नाम का हवाला देकर एक बात कही। उन्होंने कहा, मैं उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं :

> "You may be knowing that the leaders of the syndicate are taking interest in this University. (Aligarh Muslim University). Shri Piloo Mody has been bestowed the life membership of the Aligarh Muslim University. Mr. Atal Bihari Vajpayee visited the University and had discussion there."

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक उस विश्व विद्यालय में गया नहीं हूं निकट भविष्य में उस विश्वविद्यालय में मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। श्री चन्द्रप्पन को सही जानकारी रखनी चाहिये। इस सदन में आकर इस तरह की अनर्गल बातें कहना या तो मुझे बदनाम करने का तरीका है, या मेरी पार्टी को बदनाम करने का तरीका है। किसी प्रेस में यह छपा हुआ नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात है। सी० पी० आई० के मेम्बर इस तरह की अनर्गल बातें कह कर देश के वातावरण को बिगाड़ना चाहते है।

13.25 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74—Contd.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND DEPARTMENT OF CULTURE —contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Education and Social Welfare and the Department of Culture.

Shri Mulki Raj Saini to continue his speech.

श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून) : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सरकार ने शिक्षा के प्रसार के लिये और शिक्षा को गरीबों तक पहुंचाने के लिये कुछ दिशा बदलनी है और उनकी यह योजना प्रशंसनीय है। देश के अन्दर 1971 से राज्य सरकारो को 30,000 टीचर्स, 240 इंसपेक्टर और 1000 वर्किंग टीचर्स दिये गये। इसी तरह मे 1972 और 1973 में 90,000 टीचर्स 720 इंसपेक्टर्स और 3,000 वर्किंग टीचर्स दिये गये हैं। जिससे आभास होता है कि 6 से 11 साल तक के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देने की योजना पूरी हो जायगी। यह कार्य प्रशसनीय है।

13.26 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

इसी तरीके से पढ लिखे अनएम्प्लायड लोगों को रोजगार देने के लिये 29 करोड रु० बजट में रखा गया है। इसी तरीके से सरकार ने तकनीकी, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग शिक्षा के वास्ते अलग अलग संस्थान खोल रखे हैं। सवाल यह होता है कि इन संस्थानों में किस के बच्चे पढ सकते हैं ? क्योंकि यह बहुत खर्चीली शिक्षा है इसलिये इनमें किसी गरीब का बच्चा, निम्नतम श्रेणी का बच्चा, मध्यम श्रेणी का बच्चा, हरिजन, आदिवासी और देहात के गरीब तबके के लोग नहीं जा सकते हैं। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि सरकार को यह शिक्षा गरीब के बच्चों तक पहुंचाने के लिये सस्ती करनी चाहिये। आप कहेंगे कि छात्रवृत्तियां हैं। लेकिन वह इतनी कम हैं कि इस मांग को पूरा नहीं करतीं। तो इस तरीके से सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

देश में जो शिक्षा चल रही है उसमे तीन, चार प्रकार के विद्यालय हैं । एक वह है जिन्हें हम स्वर्ग की शिक्षा कह सकते हैं, अगर कही स्वर्ग है तो । सैनिक स्कूल हैं, दून स्कूल है और भी अन्य पब्लिक स्कूल हैं जिनमे पाच, छै सौ रु० एक लडके पर खर्च होता है, इसलिये उनमें गरीब का बच्चा नही आ सकता । सरकार ने पिछले साल 25 सीटस ऐसे स्कूलो मे देने की बात कही थी । लेकिन यह तो ऊट के मुह मे जीरा वाली बात है । यह समस्या कैसे हल होगी ? देश मे समाजवाद लाने के लिए शिक्षा मे समता लाना बहुत जरूरी है । शिक्षा के अन्दर भी एक प्रकार से मौनोपोली हो गई है । मौनोपोली हाउसिस की हम बातें करते हैं आर्थिक क्षेत्र मे, औद्योगिक क्षेत्र मे । लेकिन शिक्षा के क्षेत्र मे भी मौनोपोली क्लास कायम हो गई है और इसी क्लास के बच्चे ही सबसे अधिक फायदा उठाते हैं और वे ही सही अर्थों मे शिक्षा ग्रहण करते है । में नाम देकर बताता हू । किन के बच्चे जाते है इन बडे बडे स्कूलो मे, पूजीपतियो के, उद्योगपतियो के, उनके रिश्तेदारो के, बड बड अफसरो के और अब एक नई क्लास भी बडें बडे मिनिस्टरो की कायम हो गई है, उनके बच्चे जाते हैं । उसके बाद कौन जाते है जो इन लोगो के साथ लग हुए है स्मगलर्ज, ब्लैक मार्किटर्ज, एडल्ट्रेशन करने वाले और रिश्वत पर जिन्दगी चलाने वाले उनके बच्चो के वास्ते शिक्षा की कोई समस्या नही है । जहा इनके बच्चे पढते है वहा न अनुशासन बिगडता है, न वायोलेंस होती है, न हडताल होती है । शान्ति के साथ वहा सब काम होता हैं और यह क्लास पनप रही है और यह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है। बाकी देश का क्या हाल है कुछ अच्छे विद्यालय कहे जा सकते हैं लेकिन में उन्हे उच्च मध्यम श्रेणी के लाभ के लिए कहूगा कि वे हैं । इस वास्ते कहूंगा कि वहां पर टयूशन की समस्या पैदा हो गई है । जो टयूशन नही पढा सकता उसका बच्चा पास नहीं हो सकता, उसे एप्रोच से, रिश्वत से प्रवेश दिलाना पडता है । यहां पर एम एस सी में लडकों को पांच हजार या दस हजार देना पडता है । इसी तरह से मैडीकल कालेज मे प्रवेश पाने के लिए बीस बीस हजार रुपये एक लडके को प्रवेश पाने के लिए देना पडता है । कहां है मैडीकल की शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा गरीबो के बच्चो के वास्ते ? शिक्षा के क्षेत्र मे एकाधिकार स्थापित होता जा रहा है, मौनोपली हो गई है । इसको आपको तोडना होगा । यह बहुत जरूरी है ।

निम्नतम और निम्न श्रेणी के लोगो के बच्चो के लिए शिक्षा का जो प्रबन्ध है वह नरक की शिक्षा का प्रबन्ध है, उसको नरक की शिक्षा कहा जा सकता है । पढने के लिए उनके पास किताबे नही होती हैं, जहा वे पढते है वहा मास्टर नही होते है अगर मास्टर होता है और आता है तो कही हुक्का पीने चला जाता है, खाना खाने चला जाता है तो दो तीन घन्टे वहा लगा आता है । खेत मे वह हल चलाता है और आराम के लिए स्कूल मे आता है । इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर कैसे आप समझते है कि अच्छे स्कूल पढने वाले लडको के बराबर आ सकेगा, उनके स्तर पर पहुच सकेगा और शिक्षा के क्षेत्र मे समता कायम हो सकेगी । इस प्रकार से तो जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त नही किया जा सकेगा ।

विश्वविद्यालय और हायर सैकैन्डरी स्कूल के ऊपर जा विद्यालय है उनके अन्दर दादा लोग पैदा हो गए है । गरीब का बच्चा उनमे पढने के लिए या पढने की नियत मे आएगा तो उसको वे दरवाजे पार रोक लगे । उनको धमकाएगे, वायोलन्स करेंगे और अगर वह पढना भी चाहेगा तो पढ नही पाएगा, ऐसी स्थिति उसके वास्ते पैदा कर दी जाती है । शिक्षा के क्षेत्र मे यह वातावरण पैदा कर दिया गया है । कल्चरल प्रोग्राम, कोएजुकेशन, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, आदि इस प्रकार का वातारवण तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं । मा

[श्री बुल्की राम सैनी]

बाप पहला गुरू होता है। कल कहा गया है कि मां एक लाख गुरुओं के बराबर एक गुरु होती है। उनको अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए समय ही नहीं होती है। उनका जीवन बहुत ही व्यस्त रहता है रोजगार में। सिनेमाओं, होटलों, डांसगृहों, गायन-गृहों से उनको फुर्सत नहीं होती है। वहां से बालक स्कूल में आता है पढ़ने के लिए तो वहां दादा लोगों से उसका वास्ता पड़ता है। समाज में जाता है तो वहां भी इसी तरह की व्यवस्था है। इस वास्ते वायोलेन्स कहां से आता है, अनुशासन कौन लाता है इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए विद्यालयों की तरफ ध्यान देना होगा और वहीं से इसको शुरू करना होगा। जहां पर बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते है, वहां पर शान्ति रहती है, वहां अच्छी योग्यता के मास्टर होते है, अच्छा वेतन उनको मिलता है। वे फैंसी स्कूल हैं। हमारे जो दूसरे स्कूल हैं वहां कौन मास्टर आते हैं ? उस क्षेत्र को आज उपेक्षित क्षेत्र कहा जा सकता है। इसमें वे ही आते हैं जिसको कही और नौकरी नही मिलती। बहुत सी जगहो पर यह सुनने में भी आता हैं कि जो तनख्वाह उनको दी जाती है वह कम दी जाती है लेकिन दस्तखत उनके ज्यादा तनख्वाह पर कराए जाते हैं। ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों के दिल मे बच्चों के वास्ते कोई स्थान नहीं होती है और न ही बच्चों के दिल में उनके प्रति कोई सम्मान की भावना होती है। जो तनख्वाह उनको मिलती है उससे उनका गजर बसर भी नहीं हो पाता है। नतीजा यह होता है कि वे हड़ताल करते हैं, मांग पेश करते हैं, जेल जाते हैं। मैं शिक्षक रह चुका हूं। मुझे दुख होता है यह जानकर कि आज भी पच्चीस साल के बाद भी शिक्षा जिसके लिए कहा जाता है कि पशु तक को यह मानव बना सकती है या मानव में पशुता को निकल सकती है, अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में नितान्त विफल रही है। इस ओर आपको ध्यान देना होगा। बड़े बड़े प्लान आप बनाते हैं, यह स्तर पर काम भी होता है लेकिन शिक्षा में जो पहली चीज थी और जिस पर सरकार की तवज्जह जानी चाहिए थी, वह नहीं गई है। उसका बजट ऊंचा होना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं किया गया ? इसका मुझे बड़ा खेद है।

मैं नरक की शिक्षा के बारे में कह रहा था। कल भी हमारे साथी ने कहा था कि सौ लड़के किसी पाठशाला म जाते हैं तो प्राइमरी शिक्षा पास करने तक उनकी संख्या घट जाती है और हायर सैकैन्ड्री जाते जाते सौ मे से दस ही रह जाते हैं। नाम पढ़ाई में उनके भी आ जाते। लेकिन वास्तव मे सख्या बहुत ही कम होती है।

जो विषमता शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान है उसको मिटाने के लिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हू कि सरकार शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करे और जो बीकर सेक्शन है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके वास्ते शिक्षा निशुल्क बनाए, कम्पलसरी बनाए, अनिवार्य बनाए और सबको एक तरह की शिक्षा देने देने का प्रबन्ध करें। इस दृष्टि से शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना बहुत जरूरी है ताकि कुछ खानदानों की ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने की मौनोपोली न रहे और सबको समान शिक्षा मिले। इस तरह से आप कार्य करेंगे तो समाजवाद का जो हमारा लक्ष्य है, यह प्राप्त हो सकता है नहीं तो यह स्वप्न रहेगा, स्लोगन रहेगा।

हिन्दी के प्रसार के बारे में भी थोड़ा कहना चाहता हूं। कहा जाता है कि हिन्दी को प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी, इसका प्रचार करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। जिस गति से गाड़ी चल रही है, जिस तरह से अफसरों को दफ्तरों में

काम करते हुए हम देखते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई योजना इसकी है ही नही। यहा हाउस के अन्दर भी मुझे यह देखकर बडा आश्चर्य होता है और खेद भी होता है कि हमारे माननीय सदस्य जो हिन्दी जानते है, हिन्दी भाषी क्षेत्रो से आते हैं वे भी समझते हैं कि अगर वे हिन्दी बोलेंगे तो उनको हीन समझा जायगा। मैं कहूगा कि कम से कम जो हिन्दी बोलना जानते हैं और हिन्दी समझते हैं उनको तो हिन्दी मे ही बोलना चाहिए।

समाज कल्याण के बारे मे भी मैं एक शब्द कहना चाहता हू । समाज कल्याण का काम इस तरीके से चलाया जा रहा है कि कुछ लोगो को रोजगार मिले। ग्रान्ट जो विभिन्न सस्थाओ को दी जा रही है, सहायता जो उनको दी जा रही है, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग न हो, उसका सदुपयोग हो। ऐसा मालूम होता है कि पाठशालाओ में पौष्टिक आहार की जो व्यवस्था है वह शायद शिक्षको के लिए है, पौष्टिक आहार बच्चो को नही मिल पाता है। भिक्षा वृत्ति बन्द करना हो, औरतो के अनैतिक व्यापार को रोकना हो, इस काम के वास्ते विभिन्न सस्थाओ को जो रुपया दिया जाता है उन पर चैकर आपको रखना चाहिये। उसकी देखभाल आपको करनी चाहिए और इस विभाग को देखना चाहिए कि जो रुपया अनुदानो आदि के रूप मे दिया जाता है उसका सही इस्तेमाल हो।

प्रो० एस० एल० सक्सेना :(महाराजगंज): जब नये मत्री महोदय ने चार्ज लिया था और जिस तरह के विचार उन्होंने व्यक्त किये थे उनको पढ कर मुझे बडी प्रसन्नता हुई थी। मुझे आशा थी कि स्थिति मे कुछ सुधार होगा शिक्षा के क्षेत्र में । लेकिन इस बार जब मैंने शिक्षा की मद के बजट को देखा तो इसको देख कर मैं आश्चर्य चकित रह गया । यह चौथी योजना का आखरी वर्ष है । बजाय इसके कि इसके लिए एलोकेशन बढता यह और घट गया है । दस परसेंट कट लगा दिया गया है। 136 43 करोड रूपयो मे घटा कर इसको 123 14 करोड रूपये कर दिया गया है। इसको देख कर मैं हैरान रह गया । यह बहुत जबर्दस्त कटौती है । पाच हजार करोड रेवेन्यू रिसीट है और ढाई हजार करोड कैपिटल रिसीट है । 75,000 करोड मे से केवल 123 करोड ही एजुकेशन के लिए रखा गया है जोकि 1.5 परसेट हमारे टोटल एक्सपेंडीचर का है। यह बहुत ही लज्जा की बात है। हम समाजवाद लाना चाहते हैं । समाजवादी मुल्क क्या कर रहे है, इसको आप देखें। रूस की 1972 की रिपोर्ट मैं पढ रहा था। उन्होने उसमे लिखा है कि 1975 मे उनका बजट कुल मिला करके 360,000 मिलियन रूबल का होगा जिसमे से 90,000 मिलियन रूबल एजुकेशन पर खर्च होगा यानी कुल आमदनी का 25 परसेट खर्च एजुकेशन पर होगा । वहा 25 परसेट होता है और यहा केवल 1.5 परसेट। यह समाजवाद लाने का ढग नही है । डिफेस एक्सपेंडीचर से तिगुना उनका सोशल वैलफेयर और एजुकेशन पर खर्च होता है । ब्रिटेन और अमरीका जैसे देशो का भी लगभग दस परसेट एजुकेशन पर खर्च होता है । लेकिन हमारा केवल 1.5 होता है । यह अफसोस की बात है ।

कितनी कम इम्पार्टेंस हम एजुकेशन को देते है यह इसी से जाहिर हो जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का मिनिस्टर इस विभाग मे नही है । प्रो० नुरूलहसन बडे योग्य व्यक्ति हैं, उनका कैरीयर बहुत अच्छा रहा है, वह बडे डैनेमिक व्यक्ति है, आइडियाज के आदमी है । क्या वजह है कि उनको कैबिनेट रैंक नही दिया जाता ? अगर ऐसा किया जाता तो वे अपने विभाग के लिए ज्यादा पैना प्रभावशाली ढग से काम सकते थे और अपनी योजना को चला सकते थे । मैं चाहता हू कि

[प्रो० एस० सक्सेना]

मिनिस्टर आफ़ एजुकेशन का कैबिनेट रैंक होना चाहिए ।

यू० जी० सी० के बजट में 11.5 परसेंट का कट किया गया है, अर्थात् 36 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपये का कट किया गया है । इस तरह तो यू०जी०सी० के बजट में कुछ भी नही रहेगा । यू०जी०सी० का रुपया जिस तरह खर्च होता है, वह भी शर्म की बात है । हमारे 88 परसेंट विद्यार्थी 3600 कालेजों में पढ़ते हैं और केवल 12 परसेंट विद्यार्थी 70 यूनिवर्सिटीज में शिक्षा पाते हैं । लेकिन मिनिस्ट्री की 1970–71 की रिपोर्ट से पता चलता है कि यूनिवर्सिटीज पर 23 करोड़ रुपया और कालेजों पर केवल 7 करोड रुपया खर्च किया जाता है । यह बड़े शर्म की बात है । यह कोई न्याय नहीं है । मैं चाहूंगा कि जितने विद्यार्थी जहा पढ़े, वहां उनके हिसाब से खर्चा दिया जाये । फिलहाल 60 परसेंट रुपया कालेजों को दिया जाये और 40 परसेंट यूनिवर्सिटीज पर खर्च किया जाये ।

जहां तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, हम ने देखा है कि ओलिम्पिक्स में हम सब से बाटम पर रहते है । कालेजों में स्पोर्ट्स के खर्चे को कट कर दिया गया है । अगर हम उसको दूसरे कन्टीज से कम्पेयर करें, तो वह बिल्कुल निल है । मैं चाहता हूं कि स्पोर्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाये, ताकि ओलिम्पिक्स में हमारी परफ़ार्मेन्स इतनी खराब न हो ।

मैं देहात के प्राइमरी स्कूलों में देखता हूं कि लड़के जमीन पर फटे हुए टाट पर बैठे हुए हैं और एक मास्टर बैठा हुआ है, सब चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं सुनता है कि क्या हो रहा है । इस हालत में वे बेचारे बच्चे किस तरह पढ़ेंगे ? इसी लिए अच्छी स्थिति के लोग अपने बच्चों को उन प्राइमरी स्कूलों में न भेज कर नर्सरीज और किंडरगार्टेन्ज में भेजते हैं । जब तक हमारे प्राइमरी स्कूल किंडरगार्टेन नहीं बन जायेंगे, तब तक शिक्षा में हमारी प्रगति नहीं हो सकती है । चूंकि शुरू में ही लड़कों की पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, इसलिए उनका कैरेक्टर नही बनता है । इसी वजह से बाद में स्टुडेंट्स में इनडिसिप्लिन देखने को मिलती है । हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए ।

रूस में किंडरगार्टन्ज और पायनियर कैम्प्स में बच्चो की जिस तरह पढाई होती है और जो सुविधाये उनको मिलती है, जब मैं रशा गया, तो उन्हे देख कर मुझे ईर्ष्या हुई कि काश, हमारे बच्चो को भी ऐसा मोका मिले । मिनिस्टर साहब सब से ज्यादा ध्यान इस तरफ दें ।

मुझे खुशी है कि अध्यापको का वेतन बढाया गया है । मैं चाहूगा कि यह शर्त रखी जाये कि उन को बढा हुआ वेतन तब मिलेगा, जब कि वे अच्छे रिजल्ट्स दिखायगे और अपना कर्तव्य पूरा करेंगे ।

श्री दलीप सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करना चाहता हूं । इसके साथ-साथ मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा मंत्रालय का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हू कि उन्होने दिल्ली स्कूल एजूकेशन बिल पास करा के दिल्ली के हजारों अध्यापकों की सेवा की है । इस हाउस ने और राज्य सभा ने उस बिल को बहुत जल्दी और मजबूती के साथ पास कर दिया, इस लिए मैं इस हाउस और राज्य सभा का भी आभारी हूं ।

हमारे देश के शहरों में बहुत पब्लिक स्कूल हैं । लेकिन हमारा देश गांवों में रहता है । यहां की ज्यादा जनता गांवों में रहती है, लेकिन गांवों में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है । शहरों में बेशक पब्लिक स्कूल हैं

और वहां जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वे पूंजीपतियों के बच्चे हों या बड़े अफ़सरों और ठेकेदारों के, उनको कन्वेयेन्स, स्कूलों में अच्छे खाने और ब्रेकफ़ास्ट वगैरह की सब सहूलियतें दे सकते हैं। लेकिन कम से कम सब स्कूलों का सिलेबस तो एक कर दिया जाये। इसका नतीजा यह होगा कि ग़रीब आदमी का बच्चा भी वही किताबें पढ़ेगा, जो पब्लिक स्कूल में अमीर आदमी का बच्चा पढ़ेगा।

अगर हम भारतवर्ष के पुराने इतिहास में जायें, तो हम देखते हैं कि कृष्ण और सुदामा ने एक ही जगह पर, एक ही गुरु से, एक ही किस्म की शिक्षा की किताबें पढ़ी। यह अलग बात है कि बाद मे कृष्ण द्वारिका के राजा बने और सुदामा ग़रीब ब्राह्मण रहे। परन्तु सुदामा जब कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गये, तो कृष्ण ने क्लासफेलो और सहपाठी के नाते सुदामा को बहुत आदर दिया। यदि हम सारे देश मे एक ही किस्म की शिक्षा पद्धति कर दे, तो गरीबो के बच्चे भी वही सिलेबस पढेगे, जो कि अमीरो के बच्चे पढते हैं।

शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ़ अमीरो के बच्चो के ही दिमाग होते है। दिल्ली से पच्चीस मील दूर दिल्ली–हरियाणा बार्डर पर अपने हल्के के एक गाव मे मैं इलैक्शन के सिलसिले में गया। वहा मैं ने एक लडके को कुर्ता पाजामा और साधारण खेस डाले देखा। वह जुलाहे का लडका था। उसने मुझे बताया कि वह आई०ए०एस० के काम्पीटीशन में सिलक्ट हो कर ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। इससे ज़ाहिर है कि ग़रीबों के बच्चों के भी दिमाग होते हैं। लेकिन उनकी पढ़ाई, शिक्षा पद्धति और सिलेबस में फ़र्क होता है। मैं चाहूगा कि मंत्री महोदय इस तरफ़ ध्यान दें और उस फ़र्क को खत्म करने की कोशिश करें।

पिछले दिनों मैं दिल्ली के एक कालेज में गया, जिस में को-एजूकेशन है, लड़के-लड़कियां साथ-साथ पढ़ती हैं। उनके सालाना फंक्शन में उनके डिसिप्लिन की हालत को देख कर मुझे बहुत दुख हुआ। वहां प्राइज डिट्रब्यूशन हो रहा था। जब कोई लड़की प्राइज लेने के लिए आती थी, तो लड़कों की तरफ़ से हूटिंग होती थी। मुझे बहुत शर्म आई और वहां बैठना भी मुश्किल हो गया। अगर हमारे विद्यार्थियो की डिसिप्लिन की यही हालत रही, तो पता नही, हमारे देश का क्या हश्र होगा।

शिक्षा मंत्रालय की बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है। शिक्षा मंत्रालय ज़िम्मेदार होता है नेशन और समाज को बनाने का। क्या मंत्री महोदय कालेज में डिसिप्लिन की तरफ ध्यान देंगे? मैं जानता हूं कि राजनैतिक पार्टियां यूनिवर्सिटीज के मामलों में दखल देती हैं और वहा स्ट्राइक वगैरह कराती हैं। कालेजो में पढ़ने वाली लडकियां हमारी बेटिया और बहनें हैं, जिस तरह कि लडके हमारे बेटे और भाई हैं। इसलिए यह जरूरी है कि कालेजों की बाउंडरी में इतना डिसिप्लिन हो कि कोई लडका किसी लड़की के बारे मे कोई नामुनासिब बात न कह सके। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे।

सारे हिन्दुस्तान मे कही जाइये, आपको शहरो में कालेज मिलेगे। दिल्ली मे भी शहर मे बहुत कालेज हैं। मेरी कास्टीट्युएन्सी का इलाका तीस पैंतीस मील का लम्बा चौड़ा क्षेत्र है, जिसकी आबादी नौ लाख के करीब है। मंत्री महोदय वहां एक कालेज खोलने के बारे में सोचें। अगर वह दिल्ली के देहात मे एक कालेज प्रोवाइड करने की कोशिश करें, तो मैं आभारी हूंगा।

दूसरी बात यह है कि शहरों के अंदर नर्सरी स्कूल है। छोटे छोटे बच्चे तीन साल के, चार साल के नर्सरी में चले जाते हैं और काफी उनका वहा से सुधार होता है। बचपन से ही उनको अच्छा रास्ता दिखाया जाता है।

[श्री दिलीप सिंह]

लेकिन देहातों के अंदर चाहे वह दिल्ली के देहात हों चाहे बिहार के और चाहे उड़ीसा के देहात हों, वहां पर कोई नर्सरी स्कूल छोटे छोटे बच्चों के लिए नहीं हैं। आप अन्दाजा लगाइए, गरीब आदमियों के बच्चे भी चाहते हैं कि वह अच्छी पढाई पढ़ें। तो गांवों में भी नर्सरी स्कूल खोलने की आप कृपा करें तो हमारे देश का बहुत बड़ा सुधार होगा।

एक बात मैं यह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि दिल्ली के देहात के हायर सेकेंड्री स्कूलों में, मेरी नोटिस में यह आया हैं कि बच्चों को साइंस हिन्दी में पढ़ाई जाती है। लेकिन वह बच्चे जो आइ० आइ० टी० हौजखास मे दाखिल होने के लिए प्रास्पेक्टस लेने जाते हैं तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक टेस्ट अंग्रेजी में देना होगा। अगर यह बात ठीक है तो यह डिफरेंस आप न रखें। अगर शहरों में अंग्रेजी में साइंस पढाई जाती है तो देहात के अंदर भी अंग्रेजी में साइंस पढ़ाइए और नहीं तो शहरो में भी और देहातों में भी दोनों जगह हिन्दी में पढ़ाइए ताकि वह अगर कही दाखिल होना चाहें तो उन्हें दाखिला तो मिल सके।

दिल्ली के अंदर 110 गांव हैं जिन की जमीन एक्वायर हो चुकी है। वहां पर सब लोग बेकार हो गये हैं। कोई रोजगार उनके लिए नही रहा चाहे वह लैंड ओनर्स रहे हों चाहे लैंडलेस रहे हों। शिक्षा मंत्रालय की ओर से सोशल एजूकेशन की स्कीम के अंतर्गत वहां पर कुछ सेंटर्स खोले गये थे जिसके अन्दर महिलाओ और लड़कियों को सिलाई कढाई का काम सिखाते थे। उससे थोड़ा सा रोजगार उनका बढ़ता था। अब शायद वह सेंटर बन्द करने जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली एजूकेशन डायरेक्टोरेट से बात कर के वह यह प्रयत्न करें कि उन गांवों के अंदर से जहां उनकी सारी जमीन ले ली गई है, कम से कम ये सेंटर न हटाये जायं। इनको तो वहां आप चालू रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री महादीपक सिंह शाक्य : (कासगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा और समाज कल्याण का जो विषय चल रहा है इसकी जो मांगें हैं मैं इनका विरोध तो नहीं करना चाहता लेकिन मुझे खेद है कि वह विषय और विभाग कितना विस्तृत है और उसकी मांग कितनी कम है। यह वास्तव में खेद-जनक है। समाज और शासन एक दूसरे का समवायी कारण है। समाज का निर्माण ना होता है, उसमें समाज और शासन ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि हमारा समाज अच्छा नहीं होगा तो शासन की अच्छी नही मिल सकता। यदि शासन अच्छा नही होगा तो समाज भी अच्छा नही हो सकता। इसलिये इसके लिये बजट की माग बहुत ज्यादा होनी चाहिये थी।

जैसा हमने अभी सुना है गत 25 सालों में शिक्षा का काफी विकास हुआ, काफी शिक्षालय खोले गये, स्कूलों की बाढ़ आ गई। लेकिन मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या कभी उसने इस बात का पता लगाया है कि देश में विद्यालय कितने हैं और उनमें धन्धालय कितने हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दो प्रकार की संस्थाय आज चल रही हैं, एक प्राइवेट और दूसरी सरकारी। प्राइवेट संस्थायों में क्या होता है क्या आपने अभी उसकी जांच करवाई है। मंत्री जी देख कि इनमें धन्धालय कितने चल रहे हैं, और वास्तविक विद्यालय कितने हैं ?

दूसरी खेद की बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफी प्रगति की लेकिन क्वालिटी आफ एजुकेशन जो है उसमें आप बहुत पीछे रह गये हैं। 25 वर्ष के आंकड़ों को देखते हुये यह खेद के साथ कहना पड़ता

है कि हम उसमें बहुत पीछे रह गये हैं। इसका कारण यह है कि समाज की रचना शिक्षा से होती है और शिक्षा समाज कल्याण के चार स्तम्भों मे से सबसे प्रथम स्तम्भ है। पहला शिक्षा, दूसरा समाज की समानता, तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य और चौथा सामाजिक न्याय मिलना। यदि समाज कल्याण के अन्दर ये बात होगी तो ये प्लान आपके बनते रहेंगे और ये केवल पेपर तक रहेंगें हमको इनसे वास्तव मे कोई लाभ नही होगा।

शिक्षा के लिये कहा है कि
तालीमगर नही है जमाने की हस्बोहाल
फिर क्या उम्मीद हो दौलती आराम
एहतराम

आराम तलाश करना चाहते हो और उधर शिक्षा का स्तर गिर रहा है। आज कल का पढा लिखा जवान आपसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्रियो का भूखा नही है उसको रोजगार मिलना चाहिये, वह काम की आकाक्षा लेकर शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा का आपने विस्तार किया लेकिन हमारी बेकारी चरम सीमा तक पहुच गयी है। इस पर आपने कभी ध्यान नही दिया। आज 38 करोड आदमी अशिक्षित है। एसी स्थिति मे हम चाहे कि समाजवाद आये तो यह सूर्य के सामने दीपक के प्रकाश को ले जाने के समान है। क्या आपने कभी इसका भी सर्वेक्षण कराया है कि कौन कौन से वर्ग शिक्षा से अछूते रहे है ? क्या आपने विकललागो की ओर ध्यान दिया है कि कितने विकलाग देश मे पडे हैं ? महिलाओ और विधवाओ की तरफ ध्यान दिया है ? उनके लिये क्या योजना आपने बनाई है। अनाथालयो की तरफ क्या आप का ध्यान गया है जहा अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिये ?

मेरा निवेदन है कि देश के अन्दर शिक्षा के साथ साथ बेकारी की समस्या का भी हल नही किया गया है तो समाज का कल्याण नही हो सकता।

दूसरी बात यह है कि समाज की रचना तभी हो कसती है कि जब हम ऊच नीच की खाई तो पाट दे, जब हमारे अन्दर साम्प्रदायिकता की भावना न हो, जब हम एक दूसरे क सम्मान करे। लेकिन देखने मे यह आता है कि आम जनता की बात की अलग है पार्लियामेट मे कोई स्पीच होती है तो माननीय सदस्य साम्प्रदायिक भावना लेकर कभी आर० एस० एस० की बात कभी मस्लिम लीग की बात करने लगतें है। हम सब एक है। हमारा राष्ट्र एक है। समान रूप से हम लाभान्वित हो, यह दृष्टि हमारी होनी चाहिये।

स्वास्थ्य की योजना हमारे समाज कल्याण के लिये बहुत आवश्यक है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चो के लिये अच्छा आहार नही मिलता, दूध नही मिलता। हरिजनो और गरीबो के लिये रहने के मकान नही है। उनके लिये पीने के पानी की व्यवस्था नही है। जिस देश के अन्दर पीने का पानी न मिलता हो, भोजन के लिये अन्न न मिलता हो उस देश के अन्दर समाज कल्याण कैसे होगा ?

बात और करना चाहूगा। आज जो आप यह देख रहें है कि हर जगह दर्शन होते हैं, हर जगह रेलवे की तोड़फोड की जाती है। दफ्तरो मे आग लगाई जाती है। इसका कारण क्या है ? इसका एक ही कारण है कि आज बेरोजगारी है, शिक्षित नवयुवको को काम नही मिलता। इसलिये इसको यदि आपने खत्म नही किया तो यह दीवार उठ नही सकती है।

हर हाथ हाथ को काम मिले,
हर खेत खेत को पानी हो।
तो भारत गुलशन बन जाये,
भारत मे नई जवानी हो ।।

श्री नागेश्वर द्विवेदी, (मछली-शहर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै शिक्षा तथा समाज कल्याण के अनुदानो की मागो का समर्थन करता हू। स्वतन्त्रता के 25 वर्षों के बाद जब मैं शिक्षा के मामले पर विचार कर ता हू तो देखता हू कि शिक्षालयो का बहुत अच्छा विस्तार हुआ है। चाहे प्रारम्भिक शिक्षा हो चाहे कालेज की शिक्षा हो और चाहे विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, इनका बहुत अच्छा विस्तार हुआ है। लेकिन शिक्षा का स्तर गिरा है। जिस तरह की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये उसमे हमारा कोई स्पष्ट लक्ष्य नही हो सका है। हम शिक्षा किसलिये देना चाहते हैं, हम कैसा नागरिक बनाना चाहते हैं इसमे कुछ अपने को स्पष्ट नही कर सके है। इसका परिणाम हुआ है कि एक तरफ तो स्कूलो और कालेजो मे जो लडके निकलते है वे नौकरी की तलाश मे घूमते हैं और नौकरी न मिलने पर तरह तरह के अनैतिक कार्यों मे लगते है, दूसरी तरफ वही विद्यार्थी जब विश्वविद्यालयो मे पहुचते है तो अनुशासनहीनता दिखाते है। आज शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय हो जहा पर तीन चार महीने तक वह विश्वविद्यालय उपद्रवो के कारण बन्द न रहा हो।

14 00 hrs.

सारा पैसा जो इस पर खर्च हो रहा है—लगता है कि बेकार जा रहा है। उस के साथ यह भी लगता है कि विश्वविद्यालयो मे जो छात्र पढ रहे हैं शायद उन के सामने उन का अन्धकारमय भविष्य ही है जो उन को उपद्रव करने के लिये प्रेरित करता है और इसी लिये उस को एक अखाड़ा बनाया हुआ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा प्रणाली मे परिवर्तन किया जाय और उस मे सुधार लाया जाय, अन्यथा हम उस लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र मे हमे प्राप्त करना चाहिये।

पहले धार्मिक शिक्षा की भी व्यवस्था होती थी। आज जो स्कूल तथा कालिज प्राइवेट ढग मे चल रहे है, उन मे धार्मिक शिक्षा दी जाती है। हमारा देश विधि धर्मों का देश है, यदि इन धर्मों की जो मुख्य मुख्य बाते है उन्हे हर छात्र को पढाया जाय तो मै समझता हू कि जो टकराहट धार्मिक क्षेत्र मे सामाजिक क्षेत्र मे और दूसरी जगहो पर होती है, वह बहुत कुछ कम हो जायगी। अपरिपक्वता तथा धार्मिक बातो की ठीक जानकारी न होने की वजह से टकराहट पैदा होती है—इस के लिये सरकार को हर स्तर पर प्रबन्ध करना चाहिय। मैं चाहता हू कि हर धर्म की या मुख्य बातो को शिक्षा मे स्थान दिया जाय, चरित्र निर्माण और नैतिकता की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जाय।

आज शिक्षा की जो सस्थाये चल रही है—उन मे कुछ निजी क्षेत्र मे हैं और कुछ सरकारी क्षेत्र मे चल रही है। सरकारी क्षेत्र मे कुछ जिला परिषदे चलाती है, कुछ को प्रदेशीय सरकार चलती है और कुछ को केन्द्रीय सरकार चलाती है। इस मामले मे स्पष्टीकरण होना चाहिये—यह शिक्षा किस के हाथ मे होनी चाहिये और किस ढग से चलाई जानी चाहिये।

हमारे यहा विश्वविद्यालयो मे जो इतिहास पढाया जा रहा है करीब करीब वह अंग्रेजो के जमाने का है। उन के इतिहास

का कुछ अपना दृष्टिकोण था जो उन के लिये हमारे देश में शासन चलाने की दृष्टि से उपयुक्त था । हमारे देश में नया इतिहास बहुत से लोगों ने लिखा है, मैं चाहता हूं कि उस का एकत्रीकरण कर के उस को नया रूप दिया जाय और विश्वविद्यालयों में वह नया इतिहास पढ़ाया जाय । हमारे देश का प्राचीन इतिहास आज बहुत से टीलों के नीचे बिखरा पड़ा है, संस्कृत साहित्य में भरा पड़ा है, उस की खोज होनी चाहिये । उस को निकाल कर हमारे देश का नया इतिहास बनाया जाय तो वास्तव मे सच्चा इतिहास होगा तथा उस का अनुसन्धान होना चाहिये और उस को नये सिरे से लिखा जाना चाहिये ।

संस्कृत शिक्षा की आज हमारे देश में उपेक्षा हो रही है । हमारे देश मे संस्कृत राजभाषा रही है, परन्तु कुछ लोग उस को मृत भाषा समझते है । लेकिन मैं समझता हू कि वह अमर भाषा है । उस के अन्दर शब्दों के बनाने का कारखाना है, शब्द से शब्द बनाये जाते है, धातु से शब्द बनाये जाते हैं, किसी भी शब्द को बनाया जा सकता है । लेकिन उस की पूरी उपेक्षा हो रही है, उस पर उतना ध्यान ना दिया जाता, जितना देना चाहिये । अगर हम संस्कृत की शिक्षा की ठीक से वयवस्था नही करते हैं, तो अपने देश की संस्कृत से वंचित रह जायेंगे हम अपनी साहित्यिक धरोहर से वंचित रह जायेंगे ।

हमारे यहां पहले आश्रम पद्धति से पढाई होती थी । बच्चों को शुरू से ही विद्यालयों में भेज दिया जाता था और 24 घंटे का पूरा समय वे आश्रम में ही व्यतीत करते थे । वहां उन की जीवन से सम्बन्धित हर विषय की शिक्षा दी जाती थी---मैं चाहता हूं कि उसी तरह की पद्धति फिर से चलाई जाय । आज दो-चार घंटे के लिये बच्चा स्कूल जाता है, बाकी के समय में गांव के वातावरण में रहता है । समाज के बुरे लोगों के सम्पर्क में रह कर जितना पढता नहीं है, उस से अधिक उस में दोष आ जाते हैं । इस लिये इस पद्धति को बदलने भी विचार किया जाय ।

हमारे देश में एक अमर-कोष की प्रणाली होती थी । भिन्न भिन्न क्षत्रों में ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ के वाचक होते थे, उन को कत्रित किया जाता था । हमारे यहां विभिन्न भाषाओं में अनेकों ऐसे शब्द भरे पड़ हैं, जिन को लेकर विभिन्न लिपियों में एक जगह संग्रहीत किया जाय तो आज जो भाषाओं में टकराहट होती है, विवाद होता है, वह बहुत कुछ हल किया जा सकता है । इस लिये हमें इन सम्बन्ध में एका नया अमर कोष बनाना चाहिये ।

जहां तक बुनियादी शिक्षा का सम्बन्ध है---महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को प्रारम्भ किया था, उस का प्रचार भी हुआ, सरकार ने भी उस पर जोर दिया, लेकिन वह जिस ढंग से चलाई जा रही है, एक उपहास की वस्तु बन गई है । वास्तव में जिस चीज पर मूलत: जोर दिया गया था, वह तो गौण हो गई है और जो चीज गौण थी वह मुख्य बन गई है । यदि उस पद्धति को लागू करना है तो उस ढंग से लागू किया जाय जिस तरह से वर्धा शिक्षा योजना के अन्दर स्वीकार किया गया था ।

शिक्षा के क्षत्र में भेद-भाव की पद्धति के बारे में बहुत से सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है । भिन्न भिन्न लोगों के लिये भिन्न भिन्न तरह के विद्यालय इस समाजवादी व्यवस्था में, इस धर्म निपक्ष शासन में बने रहें---यह अच्छा नहीं कहा जा सकत

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें और इस में परिवर्तन लायें ।

विश्वविद्यालयों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता बड़ी खेदजनक हो रही है । मंत्री जी ने बनारस विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो रुख अपनाया है, मैं उस का हार्दिक समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी उस पर दृढ रहें और उन के अपने जो विचार हैं, उन को कार्यान्वित करने में किसी तरह की हिचकिचाहट अनुभव न करें ।

SHRI PAOKAI HAOKIP (Outer Manipur): I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Education. One has much to say on it, but one has very limited time. The problems of students, teachers and the problem of the primary and secondary schools have always been there with us. But now within the limited time at my disposal I would like to state a few points.

According to the Directives of the Constitution, free and compulsory universal education was to be provided by 1960 but now although 13 years have passed, this requirement has not been fulfilled so far. I am very sorry to stat ethis. The hon. Minister Prof. Nurul Hasan said last year that this will be fulfilled. He said that free and compulsory universal education for the age group of 6 to 11 will be provided by 1975-76 and that of age group 11-14 will be provided by 1980-81. But I doubt whether, at the pace at which we are proceeding in the matter, we will be able to achieve that target at all

There is one other aspect to which I would like to draw the attention of the hon. Minister. We talk so much about the mid-day meals scheme obtaining in the schools. What about the poor people living in the countryside? The children of those parents living in the remote areas and the countryside are not aware of these facilities and these provisions. This should be looked into. I would like to know as to what the Government is doing in the matter. In regard to the fulfilment of educational requirements, the Government has been failing. I am sorry to state this. What is the reason? As many hon. Members have pointed out, this should have been dealt with as a national subject and this should have been decided at the national level. But this subject is divided into two parts, one looked after by the Centre and another by the States. Cannot the Centre come into the picture fully? At the same time, the State themselves cannot adequately tackle this problem. What has happened during the last 25 years is this. The allocations made for Education were very very meagre and this is one of the causes why there has been no improvement in the educational field. Here. I would like to mention one thing. This subject should be taken away from the Concurrent List and this subject should be handled by the Union for a certain time, and when the Central Government thinks that it is time, then it can be re-included in the Concurrent List. If this is done that way....

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not in the Concurrent List.

SHRI PAOKAI HAOKIP: Certainly. Something is in the Concurrent List.

This country is one of the largest democracies in the world. Unless education is improved, how do you expect the Government to function smoothly? We have taken various socialistic measures. Our people are illiterate mostly. They are not provided good leadership. Unless we improve the standards of literacy of the people, we will not have good leadership at various levels. I would like to say here that I am happy that the report for 1972-73 has contained so many changes, and at the same

time, there are many things on which the report is silent.

In this regard, I am happy to note that the Government will be bringing forward soon a Bill to establish a Central University with Headquarters at Shillong. This will help in the improvement of standards of education.

I would also like to make one request to the hon. Minister. Speaking from my point of view, being a Member from the State of Manipur, I would like to say that the establishment of a University there has been a long-felt need. Now, Manipur has become a State. It needs so many things for its development, like roads, railways etc. The establishment of a University is also very essential. I hope the hon. Minister will keep this in mind. I now sit down.

SHRI A. K. M. ISHAQUE (Basirhat): Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Education.

I avail this opportunity to put some questions to our hon. Minister. What is our educational policy? Have we framed any educational policy till now? If we have got an educational policy, what are its aims and objectives? Is it merely to produce some job-seekers or to prepare the students to enter the life of reality with confidence? If the purpose is to prepare the students to enter life with confidence, then, how far we have succeeded in that approach?

Sir, as things stand today, we find that lakhs of boys are passing the matriculation examination, school-final examination etc. They are given some lessons—some book lessons. Some of them who are rich can enter the colleges. Those who cannot afford to enter into colleges, find themselves totally helpless before the society. A vast multitude of people, joining the unemployed community every year, is creating a volcanic situation in the country. Our educational system has helped that situation to grow. The pupils are not taught so that they could be useful citizens of India. In the early fifties we heard about what is called basic training centres. We now find that nothing has been done in this regard. I do not know what has happened to our education. Why has this basic training scheme been shelved all over our country? I want to know from the hon. Minister as to what is the aim of our education policy? Is it to develop the mental faculty of the students so as to allow themselves to think for themselves or is it for merely producing the imitating people who are believers in lottery?

Sir, we have got to-day a peculiar system of examination in our country. That system of examination is not capable in determining the merit or calibre of a student. Chance element is preponderating in that system. A student of an ordinary calibre fares better or passes in the examination if he prepares the questions per chance on the previous night which are set in the examination. A very intelligent student, on the other hand, who did not, per chance, prepare himself on the question set for examination on the previous night fares badly. That means, they are dependent on mainly on the chances. That is no criterion for determining the merit or calibre of a student. This system of education was introduced by our imperialist rulers; they just wanted to produce some job-seekers to serve them. They do not want that they should go in for original thinking. Are we satisfied if we produce only job-seekers?

I want to know from the hon. Minister as to what we have done to de away with the imperialistic system of education? Has this Government been able to produce disciplined citizens in this country? As you see today, in this country, discipline is perhaps the last word in every academic institution. Why During the last twenty-five years, why we could not introduce discipline among the students in the schools and colleges? Discipline is necessary. If we could do that, that

[Shri Paokai Haokip]

would have been the best strength of our country. I would request the Ministry to make a heart-searching in regard to this and to find out as to how we could produce disciplined boys in the schools and colleges.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not only the Minister, but all of us have got to do that.

SHRI A. K. M. ISHAQUE: Sir, we are seeing that the Government has been pursuing a policy of gradual encroachment in the day-to-day administration of academic institutions. I would request the Government to give up this gradual encroachment in the day-to-day affairs of the administration. Does this country belong to 800 and odd Members of Parliament or members of the administration of this country or the country belongs to 55 crores of people. You must trust the teaching community. Why should you not allow them to function in their own way? If you allow them to function in their own way, in my view, that would contribute to the growth of this country very much. I plead with the Government that they should allow them to function independently. That is the only policy that we can follow. My last question to the hon. Minister is: How far has our policy been successful in the matter of availability of the thinkers in the country?

Sir, you know that Vidyasagar came from a very low family; Nazurul Islam came from a very poor family. Is our policy framed this way, as to find out the genius of India and utilise it for Indian purposes, to make India stronger? As you know, thousands and thousands of brilliant boys, only because they were born in poor families, could not come up, and they could not contribute to the growth or development of India. I would like to know from the hon. Minister what the Government's policy is to help this genius to be utilised for Indian purposes.

Lastly, I would like to ask the hon. Minister whether he knows that Raja Ram Mohan Roy was a great reformist. He will perhaps agree with me when I say thtat Raja Ram Mohan Roy is the father of Indian renaissance. Has anything been done to Commemorate his memory in this country? The hon. Minister knows the feeling of Bengalis. The Government of West Bengal wants to commemorate his memory by having a memorial for Raja Ram Mohan Roy. Ram Mohan Roy's house is there, and it can be turned into a national memorial to Raja Ram Mohan Roy, and the State Government has been requesting the Centre, persistently requesting the Central Government, to acquire that building to commemorate the memory of Raja Ram Mohan Roy. Even the hon. Minister, when he was in Calcutta, spoke about turning this into a national memorial. I want to know from the hon. Minister how it is that we are not having anything in this country to commemorate the memory of a great reformist and the father of Indian renaissance.

With these words, I support the Demands for Grants.

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की अनुदानों का समर्थन करता हूं। लेकिन दुख के साथ कहना पडता है कि इतने बडे देश के लिये यह जो बजट है वह कम है। आज कल देश में दो प्रकार की शिक्षा हो रही है—एक शिक्षा हो रही अफसर बनाने की और दूसरी क्लर्क बनाने की। अफसर बनाने के लिये पब्लिक स्कूल हैं और क्लर्क बनाने के लिये म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कल हैं। मतलब यह कि शासक वर्ग और शासित के लिये यह पढ़ाई हो रही है। कहते हैं कि देश में 25 वर्ष के बाद शिक्षा बढ़ी है। लेकिन हमारा कहना है कि शिक्षा जैसी बढ़नी चाहिये थी वैसी नहीं बढ़ी है। आज कल-कारखानों

में, जहां देश के निर्माण का सामान पैदा होता है, शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था के कारण, हड़तालें चल रही हैं। सरस्वती के मन्दिरों में जहां देश के नागरिकों का निर्माण होता है वहां आगजनी हो रही है, जातीयता का आधार बना हुआ है, दल बन्दी हो रही है, तथा और परेशानियां हैं, लडकों में असतोष है । उन में न गुरु और न मा बाप के प्रति आदर की भावना है । अगर शिक्षा का यही आधार रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा।

जैसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहले हमारा शिक्षा का आधार था उत्तम खेती, मध्यम वान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान । हम लोग नौकरी नही करना चाहते थे, यह भिक्षा के बराबर है, लेकिन आज उसी के लिये होड़ लगी हुई है । कारण यह है कि शिक्षा के अन्दर जो पढाई होती है उस की वजह से लड़कों का स्वास्थ्य नही रह जाता है कि वह श्रम कर सके । श्रम के प्रति उन में अरुचि हो जाती है, शारीरिक मेहनत की ओर ध्यान नही दिया जाता है जिस से बाप, मां की सहायता कर सके, गाय बैल को पाल सकें । इसलिये मेरा सुझाव है कि शिक्षा मंत्री इस बात की व्यवस्था करें कि कम से कम दो प्रतिशत कालेज और युनिवर्सिटी के जो लड़के हैं, उन के लिये समाज सेवा आवश्यक हो । इस से उन में श्रम की भावना पैदा होगी, वे श्रम करेंगे और श्रम की पूजा होगी जिससे देश का निर्माण होगा और हम प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, उन का चरित्र भी बनेगा । जब तक श्रम की तरफ नहीं जायेंगे और आदमी को ईमानदार नहीं बनायेंगे तब तक देश के अन्दर जो आज परेशानी पैदा हो रही है वह दूर नहीं होगी ।

इस के साथ पब्लिक स्कूल में और जो और स्कूल हैं जहां हड़तालें हो रही हैं, ऐसे पब्लिक स्कूलों को आप बन्द कर सकें तो बड़ा अच्छा होगा । अगर न बन्द करसकें तो फिलहाल जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां पर पढाई की कोई व्यवस्था नही रह गयी है, जैसा लोगों ने कहा कि स्कूलों की हालत क्या है, उन स्कूलों का सारा पैसा उपेक्षित और पिछड़े क्षेत्रो में भेजा जाय और इन स्कूलों को पब्लिक स्कूल के स्टैन्डर्ड पर लाया जाय, और उन पर पैसा खर्च किया जाये । जब तक आप ऐसा नही करेंगे तो इन लोगो में हिंसा की भावना रहेगी, और जो समाजवाद की रचना हम करना चाहते हैं उस में हम बराबरी का दर्जा नही दे सकेगे । इसलिये यह पैसा उपेक्षित क्षेत्रों में आप खर्च करें ।

प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल हो, और दो, तीन गावो को मिला कर एक जूनियर हाई स्कूल हो, प्रत्येक गांव में लडकियो का स्कूल हो और ब्लाक स्तर पर इटरमीडियेट और हाई स्कूल हो तथा जिला स्तर पर कम से कम एक डिग्री और पोस्ट ग्रैजुएट कालेज होना चाहिये तथा 100 मील के एरिया में एक युनिवर्सिटी होनी चाहिये । हमारा बलिया जिला, जो आजादी के लिये कुर्बानी देने में सबसे आगे रहा है, आज तक एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है । पटना में जो कि 100 मील की दूरी पर है एक विश्वविद्यालय है, इसी तरह गोरखपुर में विश्वविद्यालय है, बनारस में भी जो कि 100 मील के फासले पर है एक विश्वविद्यालय है, लेकिन बलिया, आजमगढ और गाजीपुर के लिये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है । तो मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि बलिया में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये ।

आप ने दो स्कीमें लागू की है जो लेबर ओरियेन्टेड हैं । आप ने हमारे सूबे को छोड़ दिया है । एक एक्सटेसिव डिवेलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट की स्कीम है और दूसरी एजूकेशनल डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट है । तो डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट में यू० पी०

[श्री चन्द्रिका प्रसाद]

में आप ने सिर्फ सुल्तानपुर को लिया है, हमारा कहना है कि बलिया, आजमगढ और गाजीपुर मे भी इस योजना को लागू करना चाहिये । ऐक्सटेंसिव डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट मे आप ने यू० पी० को छोड दिया है मेरा निवेदन है कि इस योजना को यू० पी० मे भी लागू करना चाहिये ।

इसी तरह से हरिजनो की सख्या हमारे यहा काफी है लेकिन आज तक एक भी हरिजनो का होस्टल नही है ? मै चाहूगा कि कम से कम एक होस्टल हरिजनो का यहा पर होना चाहिये ।

हमारे पूर्वी जिलो में एक ही लडकियो का डिग्री कालेज है, लेकिन यू० जी० सी० की तरफ से उस को कोई सहायता नही दी गयी । उसके लिये हम बराबर प्रयास करते रहे और इस काम मे हमारा दो, तीन हजार रुपये भी खर्च हो गया लेकिन आज तक कुछ सहायता नही मिल सकी, यह बडे दुख की बात है ।

हमारे साथियो ने कहा कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । मै मानता हू कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, लेकिन उस का राजतन्त्रीकरण नही होना चाहिये । आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा है कि बच्चो का दिमाग एक क्लीन स्लेट की तरह है उस मे किसी जाति भावना को नही भरना चाहिये बल्कि उस का मस्तिष्क खुला रहना चाहिये ।

पब्लिक ओरियेन्टेड और पब्लिक पार्टिसिपेशन से कालेज चल रहे है जो सारे खराब नही हैं । मैं जानता हू कि हमारे यहा एक यहा मनोहर ट्रस्ट कालेज है उस मे टीचर्स को हर महीने समय पर तनख्वाह मिलती है, यहा पर अच्छी तरह से काम चल रहा है, कोई स्ट्राइक नही होती है । ऐसे अगर विद्यालय हैं तो उन को सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिये । अध्यापको के लिये कम से कम गारन्टी होनी चाहिये, उनकी सोशल रेपासिबिलिटी सरकार को लेनी चाहिये और उन को कोई कठिनाई नही होनी चाहिये ताकि वह ईमानदारी से और मेहनत से काम कर सकें ।

कुछ साथियो ने भाषा के बारे मे कहा है । इस सिलसिले से मेरा निवदन है कि हमारी भी भोजपुरी भाषा है जिस को चार करोड लोग बोलते हैं लेकिन उस के बारे मे आज तक कुछ नही किया गया । जब कि इस भाषा के बोलने वाले डा० राजेन्द्र प्रसाद जी थे, माननीय जगजीवन राम जी हैं, श्री जयप्रकाश नारायण है लेकिन उस भाषा के बारे मे कोई रिचर्स नही की गयी । यही नही ज्योतिर्ष के जनक भृगु जी, जिन्होने भृगु सहिता लिखी है, भोजपुरी भाषा बोलने वाले थे । इसलिये मेरी माग है कि उस भाषा के विकास के लिये भी सरकार को कुछ करना चाहिये ।

इस साल हम स्वतत्रता की रजत जयन्ती मना रहे हैं लेकिन हमारा बलिया जिला जो कि आजादी की लडाई मे सदा अग्रणी रहा है, और 1857 की आजादी की लडाई का प्रथम सेनापति कुवर मगल पांड रहा है, उस के नाम पर आज तक कोई स्मारक नही बनाया गया । जिला स्तर पर कोई स्मारक नही है । मेरी माग है कि इस ओर सरकार को कोई कदम उठाना चाहिये ।

आज हमारी शिक्षा धर्म की मर्यादा और भारत की प्राचीन सभ्यता पर आधारित होनी चाहिये और जो भारत की मान्यताय है, सत्य और अहिंसा की जब तक शिक्षा जो उनके अनरूप नही लायेंग तब तक हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा नही होगा । हमारी शिक्षा लेबर ओरियेन्टेड होनी चाहिये, जौब ओरियेन्टेड होनी चाहिये तभी भेदभाव मिटेगा और बच्चो मे फैला हुआ असतोष दूर होगा ।

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): Sir, first of all I should like to express my very deep sense of gratitude to the hon. members for the deep interest they have shown in the development of education, social welfare and culture. The number of hon. members who have participated in the debate is unusually large, so that the time allocated for discussion had to be increased by you with the approval of the House. The level of the debate, as you yourself have seen, has been extremely high and at the level mainly of policies. The suggestions which have been given by the members will be of immense value to us in the finalisation of the fifth plan. I am particularly grateful for the kind references that have been made to me and my colleagues in the ministry. All this has touched me deeply and I feel immensely grateful. I can assure the hon. members that we in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture will do everything that lies in our power to deserve the confidence which the House has reposed in us.

The points that have been made broadly cover three categories. The first is the category relating to broad policy questions. The seceond refers to some major events or issues which have to be dealt with by me in the House. The third covers a number of issues which are important or points on which some clarification and information is sought, but which nevertheless are limited in their scope. I would have liked to refer to all the three categories, but in view of the fact that the time at my disposal is limited, I will beg of the House to pardon me if I deal with the first two categories of general policy and specific points which need to be immediately referred to in this House. So far as the rest are concerned, I shall be writing to individual members giving them the information or comments of Government and I would crave your indulgence to be excused. It is not as if I consider those points to be less important, but I have to look at the clock and the time-table of the House.

I will deal rather briefly with the basic problems of social welfare and culture and then take up education on which much more has been said in this House. First of all I would like to make a reference to the education and development of scheduled castes and scheduled tribes. Even though the subject of the development of scheduled castes and scheduled tribes, including post-matric scholarships, is now the responsibility of the Ministry of Home Affairs, my ministry is deeply conscious of its responsibility of looking after the welfare of the weaker sections of our community, particularly educational opportunities for them and in particular of the scheduled castes and scheduled tribes. We shall be making every effort to see that the educational opportunities available to the scheduled castes and scheduled tribes and the other deprived social groups are fully taken into account. In this connection, I would like to make specific reference to admissions to the Indian Institutes of Technology. In spite of the fact that a 20 per cent reservation already exists, due to certain difficulties this quota was not being fulfilled. The Council of the IITs reviewed this question and expressed its great anguish at the fact that the full quota reserved for scheduled castes and scheduled tribes was not being fully utilised. Therefore, we are proposing to make certain changes in the rules, so that when the next admission takes place in July, this quota is fulfilled. This is just one of the examples because some hon. Members have referred to IITs.

My task in this respect has been considerably lightened by the intervention of my colleague, Professor D. P. Yadav. I will, therefore, not like to repeat the points to which he has already made a reference.

[Prof. S. Nurul Hasan]

A great deal of attention was paid to the fact that we have not yet issued a Children's Policy Resolution and appointed the National Children's Board. This is perfectly true. It is a charge to which I plead guilty. My only justification is that if this resolution is to be acted upon, it would require consultation and being fed into the Plan. Therefore, until suitable provisions are made in the Plan it would perhaps be rather unrealistic for the government to issue this resolution. But, at the same time, none of the major programmes for the welfare of the children have been held back. They are still going on and they are being increased in a massive way.

I would particularly refer to the nutrition programme for children and to the pre-school education of children between the ages of three and six. One of my friends referred to the fact that the children of the rich can go to kindergarten. But the programme of educating children from three to six and providing them with pre-school education is to be confined to the weaker sections of our population, particularly in the villages. We hope that the primary school will be the nucleus where this will be done. The nutrition programme has already been referred to by my colleague. An integrated programme is being worked out and, to some extent, the implementation of this has already started.

In regard to the question of culture, I can assure the hon. House that we are deeply conscious of our responsibility of preserving our ancient monuments and the ancient heritage of this country. I can assure the House that this work will not suffer for want of funds. In the Fifth Plan we propose to include a scheme under which both the Centre and the States will undertake thoroughly massive programmes for the conservation of monuments in their respective jurisdiction. It is also proposed to develop monuments with landscape gardening of appropriate type. Naturally, emphasis will also be laid on chemical preservation of the monuments and of the paintings and murals in these monuments.

We are also launching now a scheme which the Survey had wanted for a long time but which, for some reason or other, could not be implemented, and that is the village to village archaeological survey. We are now attempting a new project, and that is involving the students in this work. We feel that MA students in history and archaeology can be given suitable training and can be involved in this work. If we are able to mobilise this student power, it should not be impossible for us to complete the village to village survey within the Fifth Plan period.

The hon. House will recall having passed the Antiquities and Art Treasures Bill of 1972, which has become an Act. We are taking urgent measures in order to frame the rules to set up the proper staff for registration of antiquities, and more than that, to train the CBI and the Customs officers, so that they are able to prevent smuggling or unauthorised trade in antiquities. The State Governments have been giving us full cooperation in setting up the implementation machinery.

Naturally, the efforts in the field of archaeology have to be strengthened by major repositories of cultural heritage such as museums, libraries and archival holdings and centres. We want to strengthen the Central museums. We also want to give assistance to well established libraries, particularly of manuscripts. In this connection, I would, specially, like to make a reference to the offer which the Central Government have made to the Government of Tamil Nadu in order to assist the Government of Tamil Nadu in looking after that most magnificent collection of manuscripts at Tanjore. I hope, it would be possible for the Government of Tamil Nadu to take advantage of the offer of the Central Government.

We are equally conscious of the fact that museums, howsoever important they may be in the national sector and in the State Capitals, nevertheless have a role, as have the libraries, the role, to play in developing the consciousness of the masses of our people. We are, therefore, making plans to take the museums of culture as well as of science and libraries as far as the Block headquarters during this Plan. Now, I cannot make a definite commitment to the hon. House because the plan has not yet been finalised. But this is the proposal on which we are working and depending on the resources that are available to us, we will attempt to do our best.

I would like to make a very brief reference to the akademies. I would not like the charges made against the akademies to go uncontradicted. Akademies have done, within the limited resources available to them, extremely valuable work. But I do share the feeling expressed in this House that they must improve their working in order to cope with their responsibilities which are now being felt more and more by the nation. It is also necessary that State akademies should be established where they do not exist and be strengthened where they do exist. We are hoping that in the Fifth Plan the situation will be rectified and that the chief recommendations of the Khosla Committee to strengthen the State akademies would be accepted and funds would be made available.

Sir, the development of Indian culture is a matter of the highest importance for us. Our culture has its own distinctive features. It has grown out of many streams which have given it its unity in diversity, which has given to the world that pattern of cultural synthesis which is almost unique, which has a tradition of tolerance and large-heartedness, which is so characteristic of the Indian people, which at times gives the impression of syncretism and eclecticism, but which, nevertheless, has a higher dialectical logic to weld it into a basic unity while retaining its diversity which we all wish to preserve because it lends so much colour to it. This has to be preserved, this has to be developed. We cannot afford an attitude towards culture which is only past oriented. We must see that our culture rooted in the past blossoms out to solve the needs of the masses of our people for the future. We cannot afford the luxury of having two cultures—one a science culture and the other a culture of non-science. The two have to be welded in acoordance with the particular genius of the Indian people with the new technique which has been evolved by the Indian people to absorb new ideas and to keep the windows open as Gandhiji said, but not to be swept away by the winds which come through these windows. Therefore, a cultural policy has to be evolved. It cannot be dictated to by a group of us. It has to be evolved by a general consensus and I hope that the contributions made in this hon. House will lead to the emergence of such a cultural policy.

A reference was made to the international cultural agreements. It is true that we have 26 formal cultural agreements but the executive cultural exchange programmes are not confined only to these 26 countries. During the last year we have made special efforts to arrive at executive programmes with countries in Asia. We have evolved such programmes with Bangla Desh, Mongolia, Afghanistan and the Arab Republic of Egypt. We hope we will be able to extend this programme.

I now come to a point which has been repeatedly raised, that is to say, the reduction in the Budget. What the hon. Members have said has really raised my morale. I was a little upset that what we wanted and what we considered to be the minimum was not being given to us. But one has to bear in mind certain constraints which the Planning Ministry and the Finance Ministry have to bear. It is

[Prof. S. Nurul Hasan]

not that they were happy at cutting down the allocations for education or that they are not conscious of the importance of education....

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): But, why do you think of education all the time wherever there is a cut?

PROF. S. NURUL HASAN: Many sectors have been cut but this point has been....

SHRI SAMAR GUHA (Contai): This is not the first time. For the last 25 years, education has been the victim whenever there is a cut.

PROF. S. NURUL HASAN: But the hon. Member will bear with me. I have started with a 'but' and I think the 'but' might answer some of the questions. While the formal allocation has been cut, there have been assurances given to us that by way of advance action for the Fifth Plan, additional allocations would be made available. Then we hope to get a fairly large grant for the payment of primary teachers from the provision of Rs. 100 crores made in this year's Budget for creating five lakhs of jobs for the educated unemployed. Moreover, if we are short of funds and if we find that any on-going programme is likely to suffer, then I will come before the House for a supplementary grant and I am sure the House will give my request as sympathetic consideration as it has given at the moment and sympathise with me in the cut ....

SHRI SAMAR GUHA: We will happily do that.

PROF. S. NURUL HASAN: I believe that this financial stringency will be temporary and be limited to the current year only.

I think it would not be out of place for me to mention here that comparatively larger funds have been allocated for education in the proposed Fifth Five-Year Plan. In the First Plan, Education received Rs. 153 crores or 7 per cent of the total outlay. In the Second Plan it received Rs. 273 crores or 5.8 per cent of the total outlay. In the Third Plan this allocation rose to Rs. 584 crores or 6.9 per cent. In the Fourth Plan the allocation was Rs. 824 crores or only 5.2 per cent of the total. Now, in the Fifth Plan, the total allocation proposed for Education is Rs. 2200 crores or 6.4 per cent. The proposed allocation in the Fifth Plan exceeds the total allocation in the first four Plans put together. This shows that the Government is deeply conscious of the role of education.

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) . प्वाइंट आफ आर्डर सर। मान्यवर, शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, गाव गांव में स्कूल खोलने की आवश्यकता है ...

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order. Kindly sit down. Nothing will go on record.

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे . * *

PROF. S. NURUL HASAN: I would like to refer to one specific point because I think, I should make a public statement in Parliament as early as possible. This is with regard to the selection grades of trained graduate teachers in Delhi. I deeply regret to inform the House that there has been an unfortunate error in the list of trained graduate teachers in Delhi who were promoted to the Selection Grade. It is an unfortunate fact that some of the teachers whose names were there in the list have either resigned or died or had gone abroad, etc. The error has to be regretted and the Delhi Administration have called for the explanation of the persons responsible

**Not recorded.

for it. Such names have since been deleted from the list and the resultant vacancies have been offered to eligible teachers next on the list.

Sir, several hon. Members have referred to the position of teachers including the need to improve their social and economic status and to give them security of tenure whether they are working in private institutions or elsewhere. Being a teacher myself, I would naturally accept all these points. But more than that, the House has accepted the National Policy on Education, which has emphasised the crucial role of the teacher. It is the Sovereign Parliament as such, which has accepted this policy.

Sir, my acceptance of this policy is not as important as the entire House —which has only a few teachers amongst its Members—accepting this policy. I hope that as a result of the recommendations of the Pay Commission, to which a reference was made a little while ago, in the House, there would be a further improvement in the conditions of service of the teachers in the Union Territories and in the Central Schools. I also hope that the broad principles which are laid down by us, would be aceptable to the State Government also. In fact, the Chairman of the Finance Commission, has already announced that these needs of the State Governments will be given due consideration by the Commission while finalising its proposals.

So far as University and College teachers are concerned, as I already stated before in the House, the Committee appointed by the UGC on the governance of Universities and Colleges which had to finalise its report on the service conditions of University and College teachers, has now been able to complete its work. I expect to receive this report with the comments of the UGC fairly soon.

The question of the remuneration of the teachers is a very complex problem. The first effort is to give the community of teachers its appropriate status. The second is to move in the direction of a general austerity in the remuneration of all public servants, in order that economy may have an adequate chance to grow. I hope it will be possible to find a proper equilibrium between these two very important aspects of policy.

Sir, my hon. friend, Shri Dhandapani, referred to the significant achievements of the Government of Tamil Nadu, in the field of education. I have no hesitation in stating that I agree with him and I consider the educational policies of the Government of Tamil Nadu to be forward-looking policies, and I have received every cooperation from the Minister of Education of the Government of Tamil Nadu. But, Sir, the point that he raised about Tamil Nadu not getting enough teachers is contradicted by his own assertion, which I think is correct, that it is a very advanced State. If regional imbalances are to be removed, then, we have not to provide an equal distribution of resources but an equitable distribution of resources. Those who have been lagging behind, who have not been able to attain the level of development and whose resources are not adequate, must be given comparatively higher priority, compared to those who have already made adequate progress.

Sir, reference was made to the right of the linguistic minorities and of the development of Urdu. The Constitution is very clear. Every child has the right to receive his primary education through his mother tongue. This is a constitutional guarantee and the Government of India stands fully by this Constitutional provision and has been impressing upon the State Governments the urgent need to implement this Constitutional provision.

श्री विभूति मिश्र : (मोतीहारी) : उनके पास पैसा नहीं है, वह इम्प्लीमेंट क्या करेंगे ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : ऐसी बात नहीं है, पैसा है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : यू० पी० में पैसा नहीं है, इस नाते सारा काम रुका हुआ है ।

Prof. S. Nurul Hasan: यू०पी० में दे दिया है, अभी बतला रहा हूं । अरे भैया, हमहुं तो यू० पी० के है, अबहुं बतैवे ।

15.00 hrs.

It is also our policy that facilities for teaching of Urdu would be provided at the secondary level in schools wherever there is a reasonable number of Urdu-speaking students studying in the schools. Now, you will observe that there is a shift of emphasis. Formerly, in all good faith, the Central Government and the Chief Ministers had decided that wherever there is a demand, this would be done. Now we saw that in actual practice using the word 'demand', a lot of hanky-panky was done by many local officials and local institutions. Therefore, we have now taken a view that we can ascertain wherever there is a reasonable number of Urdu-speaking students.

It is on this basis that the Central Government ordered that the teaching of Urdu should be provided in 27 Central schools and the number of students who ultimately took up during the current academic session study of Urdu was 1,876, which has shown that the policy pursued by the Central Government has been justified by actual facts of the case.

The Tarraqi-a-Urdu Board has been concentrating on the production of academic literature, scientific books, children's literature and reference encyclopaedia. In the field of university education, the Board have selected 542 titles for original writing or translation. It has also been engaged in preparing English-Urdu and Urdu-Urdu dictionaries and encyclopaedias. In the field of secondary education, the Board have undertaken translation of 49 books published by NCERT, for middle and secondary classes. 20 of these have already been translated and approximately 12 of them are expected to be published by May, 1973.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Has any direction been issued to State Governments? Our complaint is that the State Governments do not accept them. We have passed resolutions. People have died on hunger strike. There is the case of Jai Bahadur Singh one of our friends who died before the UP Council. What are the instructions to the States? Urdu is an Indian language. It is not imported from a foreign country.

PROF. S. NURUL HASAN: I was first mentioning the Central Government and then State Governments.

SHRI S. M. BANERJEE: As for the Central Government, it is all right.

PROF. S. NURUL HASAN: If he is satisfied, I will not refer to the Central Government, including the problem of training teachers which we have attended to, including the assistance to non-official organisations dealing with Urdu.

So far as the UP Government are concerned, the following steps have been taken by the State Government. I have official information from the State Government of U.P. At least one Urdu teacher is to be appointed before the beginning of the next academic session in every primary school in the municipal area. It is expected that about 3,000 Urdu teachers will be appointed shortly. Such Urdu Maktabs as have been reorganised by the Education Directorate, UP, but were not included so far in the list of institutions sanctioned grant-in-aid to be immediately put on the grant-in-aid list. Facts and figures are to be collected immediately regarding such Urdu Maktabs etc. as have not been reorganised so far.

Then the Government of UP have established an Urdu Academy. The main functions of the Academy are preservation and development of the Urdu language and its literature, publishing original works of literary and academic merit in Urdu, arranging translation of Urdu literary and scientific works, preparation and publication of reference works in Urdu, provision of facilities including financial assistance for advanced study to Urdu scholars for specified periods, to give monthly financial assistance to old and needy authors of Urdu. These steps have already been taken by the Government of Uttar Pradesh .

My hon. friend Shri Banera referred to history writing. I am very much worried that there has been a gross distortion of history and a presentation of history in a manner which, if it is not questioned and challenged, would strike at the very root of India's unity. I am particularly worried as a professional student of history, because it is based on a distortion of facts and not on a scientific attitude towards history. It was, therefore, essential that history writing on scientific and objective lines should be encouraged so that our people can really understand our heritage and the historical processes which have led to the vigour and vitality of India's culture and development. It was for this reason that the Indian Council of Historical Research has been set up. No person has been appointed anywhere because of the political party to which he belongs; the only criterion has been whether he has the competence as a scholar and an approach of objectivity in dealing with history. It was with this purpose that the NCERT has brought out already three school text-books in history. I have had the privilege, before I came to occupy this office, of serving on the advisory board of the history school text-book project, and I hope that all the six volumes, three dealing with middle schools and three dealing with higher secondary, will soon be available to the public. They are already in use in the Kendriya Vidyalayas and some of the State Governments have accepted them.

SHRIMATI BIBHA GHOSH GOSWAMI (Nabadwip): What is the language?

PROF. S. NURUL HASAN: They have been published in English and Hindi, and the State Governments have been invited to translate them in their own regional languages and publish them.

Reference has also been made for taking up education as a concurrent subject and one of my hon. friends thought that it should be put in the Central list. I beg to submit that Government are not in favour of getting the whole discussion and debate on education involved in constitutional wrangles of States versus Centre or Centre versus States. It is a common task and there is a general understanding, both among the State Education Ministers and the Union Education Ministry, that we have to work together for achieving our common objectives, and it is for this reason that in the Central Board of Education which consists of all the State Education Ministers irrespective of party lines, a common strategy could be evolved. I hope that most of the recommendations of the Central Advisory Board would be acceptable to the Planning Commission in the sense that funds could be made available, and if funds are made available, I have no doubt that our policies jointly agreed upon and voluntarily agreed upon between the State Education Ministers and the Union Ministry of Education would be implemented.

Many Members have talked about the transformation of the educational system. Many Members were kind enough to refer to the fact that the Prime Minister, in several of her speeches, and I myself whenever I have had the occasion to do so, have averred that we must bring about a radical transformation of the educa-

[Prof. S. Nurul Hasan]
tional system so that it can serve the needs of our society.

Therefore, Sir, in the plans that we have formulated jointly in the Central Advisory Board if the hon. Members would agree to examine the essential features of it, they would find that definite break with the existing system would be taking place. But, I would like the hon. Members to remember one thing that if you add the number of teachers, the number of students and those who are involved in the process of education, the total would reach something like 10 crores, roughly twenty per cent of the entire population. Taking the plan and non-plan expenditure of the States and the Centre together, we are spending an amount of Rs. 1100 crores a year on education which is next only to defence expenditure. A major transformation of the educational system will, therefore, not only require the efforts of the Government of India but also the efforts of the State Governments, of the voluntary agencies, of the teachers of the students and of their parents. I am not saying that I am not accepting the responsibility. But, I am pleading for a little patience because, this is a gigantic task and so, you have to judge us whether the direction is correct; you should judge us whether we are moving with adequate speed. But, please do not expect that a miracle can be performed overnight. If we have started moving in the right direction with appropriate speed, then, I think, there would be a great deal of cause for satisfaction.

While talking of the Plan, I have already said that the allocation in the present plan is more than the total allocation in the Fourth Plan. It has also a unique feature. Firstly, it gives an overriding priority to primary education which gets an allocation of about Rs. 1100 crores or 50 per cent of the total allocation. This is a right priority in my opinion. Primary education is being put or being sought to be put in the minimum needs programme so that the amount allocated for it is not cut down. On vocationalisation of the study, a considerable outlay has been proposed and the concerned ministries are making a coordinated effort to diversify the Secondary Education, particularly, at the high school level.

Then, for the first time, it lays down a policy with regard to higher education to regulate and to conform to increasing employment opportunities for the educated and learned persons. And this, I should like to underscore, is not in any way, to curtail the free access to higher education which the persons from the deprived sections of the community, especially, the scheduled castes and scheduled tribes, have at present. In fact, it is proposed to regulate the overall enrolment in higher education and at the same time, to increase the opportunities for the higher education now available to the weaker sections of the community.

In this connection, I would like to deal with the point which my hon. friend, Shri Ishaque has made. I am sorry he is not here at the moment. That was about the goal of education. The goal of education is basically to train the minds and the hands and to bring about a coordination and to develop the faculties of the intellect and of personality and of character in a manner which would help meet any challenge with which the young man is likely to be faced in future.

Having said that, I would submit, people have to live and it is no use closing our eyes to the fact that we can keep on producing graduates, especially with general education and not look at the employment opportunities open to them. This plan puts emphasis on quality improvement at all stages. In particular, special efforts will be made to improve selected institutions at all stages.

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): We are told it will be related to employment. Now there are lakhs and lakhs of educated people without any jobs. So, if higher

education is related to employment. it means you want to curtail higher education until job opportunities are created. That is implied.

PROF. S. NURUL HASAN: That is not implied. The main point I was emphasising was that higher secondary education will come in for massive vocationalisation, so that many people will be in a position to go in for a vocation and if at a later time they wish to revert to higher education, they can always do so. Sir, I am sorry I cannot go into all those details now. Informal education, the concept of open university, correspondence courses all these will have to be taken up. These are some of the most important features of the new fifth plan and the details have been made available to hon members.

I would like to refer briefly to the point raised about the existence of public schools. The Government of India's policy has been enunciated in the National Policy Resolution on education. Firstly the common school system has to be strengthened. We cannot straightway strengthen and build up the requisite facilities in all our primary schools. Therefore, the proposal at the moment is to upgrade 10 per cent of the primary and higher secondary schools during the current plan period and also to establish model schools. The plan about model schools has not been finalised, but I would like to remove the misapprehension of Shrimati Goswami and Shri Chandrappan that these schools will cater to the upper classes. At the primary level these will be in the blocks and no fees will be charged. In fact, 25 per cent of the seats will be reserved for the poorest sections who will be paid full maintenance grants. At the district level, the fees charged would be the same as exist at the moment in Kendriya Vidyalayas, which are, as everybody knows, still open to the common people. There will be no intention to cater to the upper classes through these schools.

SHRIMATI BIBHA GHOSH GOSWAMI: What about hostel charges? It will be residential.

PROF. S. NURUL HASAN: Yes, but the residential expenditure will be kept to the minimum. It will be run on the basis of "No loss; no profit". There is no intention of following the public school system.

Then I would like to correct an impression. Most of the so called public schools are now switching over to the syllabus prescribed by the Central Board of Higher Secondary Education and they are not going in for anything else.

I have to briefly emphasize the question of work experience and vocationalisation, to which I have already made a reference. I would also draw the attention of the hon. House to the rural talent search scheme under which rural children, two per block, will be provided with scholarships.

Then, reference has been made to text-books. The NCERT has already screened about 2,000 text-books and advised the State Governments where it thought that certain changes were needed. Then, the NCERT is also undertaking the responsibility of preparation of text books which will be free from all these defects. We wish to strengthen this programme, particularly in the next Plan period.

About examination reform I have spoken several times in this hon. House. I have gone so far as to say that anyone may have faith in the existing system of education, but I have no desire to hold forth in defence of the existing examination system. I still stand by that view. We are doing our very best to persuade the State Governments. We have sent them the reports and we request them to deal with those reports.

Coming to the Central Universities, I am as concerned as many of my hon. friends about the growth of communal

[Prof. S. Nurul Hasan]

activities in the campus of BHU and elsewhere. I agree with the suggestion made by my hon. friend, Shri Chandrappan, that the whole question has to be examined in depth. The Government will certainly apply its mind in order to find out what is the best way to meet this situation. But I would like to make one point clear. Government feels very unhappy at the consistent campaigns to denigrade the Vice-Chancellor of BHU. Government has been giving, and proposes to continue to give, all support to the Vice-Chancellor and to the legally constituted authorities of the University to take all the necessary steps to ensure the academic functioning and discipline in the University.

Similarly, the Government has given, and will continue to give, full support to the Vice-Chancellor of the Aligarh Muslim University in whatever decisions he takes to maintain discipline on the campus and ensure normal academic life in the University. The Vice-Chancellor's statement about the closure of the University has already appeared in the press. Since the time at my disposal is short, I do not want to take the time of the House by reading that statement. I am, therefore, with your permission, placing a copy of it on the Table of the House [*Placed in Library. See* No. LT-4736/73.

SHRI S. M. BANERJEE: Is it correct that there are some suggestions by progressive professors and other intellectuals that some amendments should be moved?

PROF. S. NURUL HASAN: If the hon. Member would bear with me for a few minuts, I will deal with it.

The statement which has been given to me by the Vice-Chancellor contains full reasons why he has taken this particular decision. Therefore, instead of reading that statement which should take at least five minutes, I shall place it on the Table of the House. It has been published in the newspapers and hon. members might have seen it.

I have already steted that the Government has given and will continue to give full support to the Vice Chancellor in whatever decision he takes to maintain discipline and to maintain the academic life in the University.

I now want to deal with the point which has been raised by my hon. friend, Shri Ebrahim Sulaiman Sait, about the character of the University. The Aligarh Muslim University, as the Supreme Court has held, was never a minority institution in terms of artile 30, sub-clause (1) of the Constitution. Government, therefore, have no intention of changing the character of the University and accepting the contention that it be declared a minority institution in terms of article 30(1) of the Constitution. Government, as I had stated at the time we introduced the Aligarh Muslim University (Amendment) Bill, has no intention of changing the historical character of the University. The historical character of the University is defined in the Preamble, it is defined in section 4(1) of the Act, it is defined in section 5(2) of the Act, none of which has been changed. As a result of historical developments, the University Court, the Executive Council and the Academic Council consist of a majority of Muslim members. Government have no intention of altering this situation artifically. But, Sir, the House will recall, in regard to the constitution of the various university bodies, while I was dealing with the Bill in this House, I had said:

> "The bulk of the provisions are in the Statute and if, at any time, the Executive Council of the University were to feel that in the academic interest or in the interest of the University, any particular statute needs to be amended, they have only to propose the amendment and if the Government also agrees, then the Statute can be amended. Therefore, if you pass this Bill in the present form, it does not mean that no changes, even when considered necessary for the academic

development of the institution, can be brought about. This flexibility is the result of present day academic thinking not only here but in many other parts of the world."

SHRI S. M. BANERJEE: In the larger interest of the minorities, will you accept the amendments given by those Muslims, the minority community people, who do not believe in communal approach?

PROF. S. NURUL HASAN: If the hon. Member would bear with me for a few seconds....

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मे डेमोक्रेटाइजेशन ...

प्रो० एस० नुरुल हसन : साहब, सब बात आप ही कह दीजियेगा कि सुनियेगा भी। दो मिनट रह गये हैं मुझे कह लेने दीजिये। उसके बाद फ्लोर आप को हाजिर है आप कहते रहियेगा।

श्री इसहाक सम्भली : जैसा आपने बताया कि हिस्टारिकल कैरेक्टर रखने के लिये जिन चीजो को आप खुद समझते है जरूरी है, जैसे नौमीनेशन का सिलसिला खत्म करना, कास्टीट्यूशन मे डेमोक्रेटाईजेशन लाना तथा इसकी सर्टेंटी के लिये कि वहा पर मुस्लिम्म की मैजोरिटी रहेगी, क्या कोई इस तरह का अमेंडमेंट ला रहे हैं ?

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Kozhikode): It is a minority institution.

PROF. S. NURUL HASAN: As I was saying, although I do not still accept the view that the University has been deprived of its autonomy or that its constitution is undemocratic because the Joint Committee of the two Houses had without any substantial dissent accepted the provisions of the Jawaharlal Nehru University Act wherein the provision of the appointment of the Vice-Chancellor and its procedure, the powers of the Vice-Chancellor, the method of appointment of the Dean, the method of appointment of the Heads of Departments, the 21 nominations to the Court as against 20 in Aligarh, the manner of appointment of the Executive Council and the Academic Council are more or less at par and if at all there is any difference in Aligarh, it is for a greater representation to the younger teachers and to the existing students and in many respects some more democratic powers have been given. Although this is so, I, at the same time, state that in view of the fact that the Staff Association of the University has suggested certain amendments and that the academic community wants certain amendments, we will deal with it with an open mind and we would be prepared to accept any changes that the Academic and Executive Council propose (*Interruptions*) I am confining myself to the academic community. I am not prepared to treat the Aligarh Muslim University please forgive me for a little bit of sentimental reference; I have spent the best years of my life in the service of that University. I do not want it to become a football in a political playfield. I want it to be treated as a University and the interests of the University and the opinions of the University will carry greater weight with me and with my Government than the weight of any group of politicians who may be wishing to exploit the feelings of the University.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: I would like to have a clarification from the Minister.

The Vice-Chancellor is reported to have said that the academic life at the university had come to a standstill and there was no option but to close the institution for a short time. In the statement released by the Union Education Ministry, Prof Aleem (the Vice-Chancellor) has said I am reading from the *Indian Express* of today:

"Prof Aleem said a series of incidents had occurred which had made

[Shri Ebrahim Sulaiman Sait]

it impossible for various teachers responsible for looking after the academic or corporate life to function normally."

This was what Prof. Aleem has said.

But, on the other hand, the facts are that there is complete normalcy, no tension and nothing of that sort, but the report here in the press....

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, please.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: But the press report is:

"It was a day of dramatic developments on the campus of the Aligarh Muslim University, which was closed for an indefinite period this morning.

Teachers and students who had no inkling of the impending closure till late last night, woke up this morning only to be told that the University had been closed.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Sait, why do you assume that what others say is a complete lie?.... (*Interruptions*) Order, please. I will permit two or three questions only.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: The Aligarh Muslim University is going to be closed indefinitely.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your question is, I think, noted by the Minister. I will give him a chance to reply to your qquestion.... (*Interruptions*) One or two only..... (*Interruptions*) I do not understand this. If everybody gets up I will not permit anybody.

SHRI Y. S. MAHAJAN (Buldana): I would like to know if the Government has accepted my proposal to see that 100 per cent of the children of the school going age get enrolled in the primary schools, by the end of 1974-75.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is a suggestion for action.

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि प्रत्येक राज्य में एक एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाये ? यदि हां, तो यह कब तक हो सकेगा ?

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को वह फुटबाल नही बनने देंगे मैं जानना चाहता हूं कि बनारस यूनिवर्सिटी को कब तक वह फुटबाल बनायेंगे अगर उनका ओपन माइंड है जैसा उन्होंने कहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के बारे में आप निकट भविष्य में क्या करने वाले है, क्या वहां भी कोई तबदीली आप करेंगे या नही ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not understand this. We have etxended the time. We have extended the time of the debate on these Demands twice. Instead of one day, you have taken three days. Now, we have crossed over into the time of the Private Members' Business. Still, not only you, but there are so many others standing. I can allow one or two Members only.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): Sir, the people who have participated need not have put questions once again. May I know from the Minister whether in view of the fact that the South is not well-served by a Central University, the Government propose to start a University at Hyderabad so as to help in removing some of the difficulties which are being faced with regard to the Mulki rules, educational facilities and so on, and if so, what does the Government propose to do in the matter?

SHRI RAJDEO SINGH (Jaunpur): I want to know something about the proposal of the autonomous colleges.

PROF. S. NURUL HASAN: I would say that there is no proposal under consideration of the Central Govern-

ment to establish a Central University at Hyderabad. So far as the southern region is concerned a proposal given by the Government of Pondicherry to establish a Central University has been supported by the University Grants Commission and is now under the consideration of the Government. We have to look at the resources position.

All the suggestions given by hon. Members will certainly be borne in mind as I said initially, in preparing the Fifth Plan.

So far as Banaras Hindu University is concerned, I hope the hon. Member will mark my words carefully, that the suggestions given by my hon. friend Mr. Chandrappan will receive the most earnest consideration because I am equally worried about the situation which had developed and which is developing in the university. Lastly, I would like to deal with the question, raised by Mr. Sulaiman Sait as to what were the series of incidents. I would only request him to make his own enquiries. They are very well-known. The number of incidents which have taken place would not have given credit to any institution. Why is he forcing me to make those statements here?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will now put the Cut Motions that had been moved to the Demands in respect of the Ministry of Education and Social Welfare.

All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the question is :

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the order paper be granted to the President to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 25, 26 and 27 relating to the Ministry of Education and Social Welfare."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I Will now put the Cut Motions that had been moved to the Demands in respect of the Department of Culture.

All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the order paper be granted to the President to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 92 and 93 relating to the Department of Culture."

The motion was adopted.

[*The motions for Demands for Grants, which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below—Ed.*]

DEMAND NO. 25—DEPARTMENT OF CULTURE

"That a sum not exceeding Rs. 2,21,48,000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Department of Education'."

DEMAND NO. 26—EDUCATION

"That a sum not exceeding Rs. 97,98,94,000 on Revenue Account

[Mr. Deputy-Speaker]

and not exceeding Rs. 88,49,000 on Capital Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Education'."

DEMAND No. 27—DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

"That a sum not exceeding Rs. 22,09,52,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 4,17,000 on Capital Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Department of Social Welfare'."

DEMAND No. 92—DEPARTMENT OF CULTURE

:"That a sum not exceeding Rs 5,59,34,000 on Revenue Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Department of Culture'."

DEMAND No 93—ARCHAEOLOGY

"That a sum not exceeding Rs. 2,18,08,000 on Revenue Account be granted to the President *to complete the* sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Archaeology'."

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up Private Members' Business. It is assumed that Private Members' Business starts from now and two hours and thirty minutes time is allowed from now onwards.

Shri Arjun Sethi.

15.40 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Articles 62 and 65)

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN SETHI: I introduce the Bill

MR DEPUTY-SPEAKER: Shri Rana Bahadur Singh Absent

15.41 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Seventh Schedule) by Shri Arjun Sethi—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up further consideration of the following motion moved by Shri Arjun Sethi, namely:—

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

On the last occasion, Shri S. P. Bhattacharyya was on his legs. He may continue his speech.

SHRI S. P. BHATTACHARYYA: (Uluberia): The other day I spoke about the Bill. I oppose the Bill because I do not want that the authority of the State should be taken away and education made a concurrent

[*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 6-4-73.]